

परिपत्र

राज्य के अधिकांश राजस्व ग्राम, शहरी कच्ची बस्तियों तथा अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर्ड किये जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को समेकित बाल विकास सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। विभागीय प्रयासों के उपरान्त भी वर्तमान में कुछ दूरस्थ क्षेत्र एवं बस्तियां आईसीडीएस सेवाओं से वंचित हैं।

भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल रिट पिटीशन संख्या 196/2001-पीयूसीएल बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 13.12.06 को पारित निर्देशों के क्रम में "मांग पर आंगनबाड़ी" (Anganwadi on demand) हेतु पत्र क्रमांक प.1-1/07-सीडी-1 दिनांक 19 मई, 2009 द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी ग्रामीण समुदायों/बस्तियों तथा शहरी कच्ची बस्तियों में मांग पर 3 माह के अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना है, जहां 40 या अधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उपलब्ध हैं। मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए राज्य में निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के मानदण्ड

- मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे क्षेत्रों/बस्तियों में खोले जा सकेंगे जहां 40 या अधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उपलब्ध हैं।
- ऐसी बस्तियां/शहरी कच्ची बस्तियां जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत नहीं है अथवा केन्द्र से जुड़ी हुई नहीं है।
- ऐसी क्षेत्र जो राजस्व ग्राम से एक या अधिक किमी की दूरी पर स्थित हैं, वहां आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत है परन्तु वहां बच्चों की पहुंच सुगमता से नहीं हो सकती है।
- ऐसे क्षेत्र/बस्तियां जिनमें जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकें परन्तु स्थानीय समुदाय द्वारा केन्द्र की मांग की गई है।
- अनु. जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों/शहरी कच्ची बस्तियों में प्राथमिकता से मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

समुदाय की मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए स्थानीय समुदाय को जिला उपनिदेशक को सादा कागज पर आवेदन पत्र देना होगा। इस आवेदन पत्र में संबंधित जानकारी यथा-वस्ती की आबादी, आंगनबाड़ी केन्द्र में शामिल होने वाले क्षेत्र, बच्चों की संख्या, निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से दूरी, राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति का नाम तथा केन्द्र संचालन हेतु न्यूनतम आठवीं पास महिला की उपलब्धता आदि तथ्यों का उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

- जिला उप निदेशक ऐसे सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उस पर की गई कार्यवाही की पंजिका संचालित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच के लिए संबंधित परियोजना अधिकारी को भिजवाकर अंकित तथ्यों की पुष्टि करवायेगे तथा केन्द्र की आवश्यकता की विवेचना करेंगे।
- परियोजना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर जिला स्तर से परियोजनावार प्राप्त प्रस्ताव संकलित कर निदेशालय में अपनी अनुशंसा प्रेषित करेंगे।

- निदेशालय द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का संकलन कर भारत सरकार को भिजवाया जायेगा।
- भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा उस स्वीकृति से जिला उप निदेशकों को अवगत करवाया जायेगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला उप निदेशक द्वारा प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जायेगे तथा निदेशालय द्वारा आगामी 15 दिवस में ये प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रपिहित किये जायेगे।
- भारत सरकार द्वारा शेष 45 दिन में प्रस्तावों को स्वीकृत कर राज्य को भिजवाया जायेगा एवं राज्य स्तर से प्राप्त स्वीकृति जिलों/परियोजनाओं तक सम्प्रेषित की जाएगी।
- मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु संचालित की जाने वाली पंजिका का प्रारूप परिशिष्ट-“अ” पर संलग्न है।

सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय समुदाय को आंगनवाड़ी खोलने की इस नवीन प्रक्रिया की समुचित जानकारी उपलब्ध करावे। कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का तत्पन्ना से निस्तारण करे। आंगनवाड़ी के आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान में संचालित केन्द्रों से ऐसी बस्तियों को प्राथमिकता से जोड़ने का प्रयास करे। जिन बस्तियों/ग्रामों में वारतव में आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता हो, उन्हीं के प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये। इन दिशा-निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जावेगी क्योंकि यह एक समयबद्ध कार्य है। अतः उक्त दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

(Signature)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.11(3)()मो/आईसीडीएस/07/39758-908 जयपुर, दिनांक 15-06-09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महिला अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर
4. सनस्त जिला कलेक्टर
5. सनस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
6. सनस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. सनस्त उप निदेशक, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

(Signature)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

पंजिका का प्रारूप

क्र. सं.	आवेदन प्राप्ति तिथि	आवेदन की तिथि	आवेदन किया	बस्ती/क्षेत्र/जहाँ ग्राम आंगनवाड़ी केन्द्र की भांग की गई	राजस्व ग्राम पंचायत	ग्राम /	पंचायत समिति	पंजिका का प्रारूप				अन्य विवरण
								सौदीपीओ का भिजवाने तिथि	प्राप्त सौदीपीओ से वापस प्राप्ति तिथि	प्रस्ताव उचित/अनुचित	निदेशालय की अग्रिम करने तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

आवेदन पत्र का प्रारूप

1-	बस्ती/राजस्व ग्राम/शहरी कच्ची बस्ती का नाम			
2-	राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम/वार्ड नम्बर			
3-	पंचायत समिति/नगर पालिका नाम			
4-	निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम व पता			
5-	निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से बस्ती/ग्राम की दूरी			
6-	आंगनबाड़ी केन्द्र में शामिल होने वाले क्षेत्रों का नाम			
7-	बस्ती में उपलब्ध दो आठवीं या अधिक पास महिलाओं के नाम जो कार्य की इच्छुक हो			
8-	जनसंख्या विवरण			
क्र.सं.	आईटम	पुरुष	महिला	योग
1	बस्ती की कुल जनसंख्या			
2	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (All)			
3	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (SC)			
4	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (ST)			
5	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (Min.)			
6	कुल परिवारों की संख्या			
7	अनु. जाति के परिवारों की संख्या			
8	अनु. जनजाति के परिवारों की संख्या			
9	अल्पसंख्यक (Min.) परिवारों की संख्या			
10	अन्य विवरण जो आवश्यक हो			

ग्राम पंचायत की अनुशंषा एवं प्रमाण पत्र मय
सील

आवेदक के हस्ताक्षर
मय पत्र व्यवहार का पता

बाल विकास परियोजना अधिकारी की टिप्पणी
मय सील

जनसमुदाय के हस्ताक्षर